

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,  
सहकारी समितियाँ,  
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1

देहरादून दिनांक 13 दिसम्बर, 2010

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद के गठन एवं संचालन (राज्य सेक्टर) हेतु अनुपूरक मांग द्वारा प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:-4863/नियो0/सह0परिषद/2010-11 दिनांक 02 नवम्बर, 2010, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-187/XXVII (1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010, शासनादेश संख्या:-928/XIV-1/10-5(8)/2010 दिनांक 26 मई, 2010 तथा संख्या:-1402/XIV-1/10-5(8)/2010 दिनांक 21 सितम्बर, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद के गठन एवं संचालन में उल्लिखित मदों में ₹5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त धनराशि का आहरण/वितरण नियमानुसार मितव्ययता तथा आवश्यकता के अनुरूप किया जायेगा।
- (2) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय।
- (3) इस सम्बन्ध में राज्य सहकारी परिषद द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में परिषद के संचालन एवं गठन पर वित्तीय सहायता की धनराशि नियमानुसार स्वीकृति के पश्चात् ही व्यय की जाय व संस्था द्वारा केवल आवश्यक व्यय ही किया जायेगा।
- (4) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि का व्यय परिषद को अनुमन्य सुविधाओं/ मदों पर वास्तविक व्यय तथा संगत नियमों के अन्तर्गत बिलों के सत्यापन के उपरान्त ही की जाय।
- (5) उक्त धनराशि का उपयोग अन्यत्र अथवा किसी ऐसी मद में न किया जाय, जो अनुमन्य नहीं है। अनधिकृत व्यय की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- (6) अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक माह का व्यय विवरण अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम-13 प्रपत्र मर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (7) उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/ निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/ मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत

शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या:-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2425-सहकारिता-आयोजनागत-00-800-अन्य व्यय 20-सहकारी परिषद का गठन एवं संचालन-00 की मानक मद-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

ये आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या:-320(P)/XXVII-4/2010 दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)  
अपर सचिव।

संख्या:-1877 (1)/XIV-1/2010, तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबराय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा।
6. सम्बन्धित जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)  
उपसचिव।